



दैनिक

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

पंचागत के चौथे
सीजन का ऐलान...8

सिद्धार्थनगर

शनिवार 05 अप्रैल 2025

वर्ष: 12 अंक: 112 पृष्ठ: 8
आमंत्रण मूल्य 2/- रूपया

एक विश्वास....

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।

सम्पादक : राजेश शर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश 8795951917, 9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com
उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी की सराहना की, कहा वर्षों से जारी अन्याय खत्म होगा
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा



कि संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दिए जाने से वर्षों से जारी अन्याय और अत्याचार समाप्त होगा तथा ग्वाह और समानता के युग का आरंभ होगा। शाह की यह टिप्पणी राज्यासभा द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के कुछ समय बाद आई। लोकसभा ने बुधवार को विधेयक को मंजूरी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि यह विधेयक को मंजूरी देना एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से जारी अन्याय और अत्याचार के युग का अंत किया है और ग्वाह व समानता के युग की शुरुआत की है। गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ समिति अधिक जवाबदेह पारदर्शी और ग्वाह बनाए जाने वाली हैं। इससे निश्चित है मुस्लिम समुदाय के गरीबी, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, 'करोड़ों लोगों को ग्वाह देने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य संसद के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, इसका समर्थन करने वाले सभी दलों व सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

क्या 16 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की जांच कर पायेगी सीबीसीआईडी ?

दैनिक बुद्ध का संदेश सिद्धार्थनगर। 16 करोड़ 16 करोड़ 16 करोड़ आखिर कौन है 16 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का जिम्मेदार कौन है महाघोटालेबाज यह इन दिनों बुद्ध जीवियों एवं जनप्रतिनिधियों के जुबान पर चर्चा का विषय



रुपए की जांच कर पाएगी इस को लेकर लोगों के मन में ससय बना हुआ है आपको बता दें की पूरी कहानी जनप्रतिनिधियों में 37 करोड़ पर धान बेचने वाले घोटाले के बारे में 4000 किसानों का है जहां इसमें कई विभागीय कर्मचारियों ने जतन कर तूट मचाया है तो घोटाले की जांच कर रही एसआईटी 37 करोड़ के धान बेचने वाले चार हजार किसानों और विभाग से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मामले की तह तक पहुंचने और घोटाले की पटकथा लिखने वालों तक पहुंचने के लिए एसआईटी सबसे सटिफाइड लॉन्ग टर्म के खाते में आने वाले रुपये आते ही बिगिन खाता में भेजने वालों चार हजार में सबसे सटिफाइड 30 प्रतिशत किसानों की जांच कर रही है। एसआईटी टीम खेती के रकबे से लेकर पंजीकरण व बैंकिंग की तारीख, खाते में धनराशि आने की तिथि आदि की जांच कर रही थी। आप को बता दें की एसआईटी टीम किसानों के बैंक खातों की पूरी चुकी (नाम, खाता संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर) एकत्र करनी पुरा सर्च करने में लगी है। धान खरीद रिकॉर्ड (तैल पत्र, मुगान पत्र, तिथि) और किसानों के रजिस्ट्रेशन डेटा से मिलान भी हो रहा था। एसआईटी प्रभारी श्री संतर चुकीत कुमार राय जांच टीम में शामिल इंस्पेक्टर

वहीं अपने दवाब में सही कार्य करने वाले कृषि केंद्रों और ठेकेदारों के ऊपर निशान लगाकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं लेकिन यदि सीबीसीआईडी सही से जांच करती है तो विभागीय कर्मचारी बड़ी संख्या में इसके खपेट में आ सकते हैं विभागीय सुबो की माने तो यह सारी कहानी अपने आप को बचाने के लिए की जा रही है यदि सीबीसीआईडी सही तरीके से जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी सही हो सकता है जिनमें 16 करोड़ रुपये से अधिक के

अयोध्या में भव्य रामनवमी समारोह की तैयारी पूरी

भक्तों को 18 घंटे मिलेंगे रामलला के दर्शन

अयोध्या। रामनवमी का त्योहार की एक झलक पाने के लिए) हैं। देने के लिए नियमित रूप से पानी उह अर्द्ध को देर भर में मनाया जाएगा। राम नवमी को लेकर खास तैयारियां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में की जा रही हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं को राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के दौरान सहज अनुभव हो वे सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। राम नवमी के मौके पर रामलला 18 घंटे तक नक्तों को दर्शन (दिखा



का शिष्टाचार कर चलाई बिछाई जाएगी, साझा अन्वयी शिपि स्थापित किए जाएंगे और 243 स्थानों पर पीने के पानी की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या नगर निगम ने भी समारोह को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं और शहर भर में स्वच्छता और सफाई की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी से लैस एक समर्पित टीम तैनात की है।

नीट से छूट देने से केंद्र का इनकार

आब एमके स्टालिन ने सभी विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 9 अप्रैल की रात को सविधानसभ में सभी विधायकों की एक परामर्श बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) से छूट देने की राय की घोषणा को खारिज



से लान पहुंचाता है जो महंगे कोडिंग सेटों का खर्च उठा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस परीक्षा ने विशेषाधिकार प्राप्त और उच्च शिक्षित उम्मीदवारों के बीच की कluft को बड़ा कर दिया है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की सामूहिक आवाज को दशकों पुरानी मेडिकल प्रथा प्रणाली ने देश के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टालिन ने कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत के साथ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए चिकित्सा की प्रवृत्ति करने का सपना आभासी हो गया है क्योंकि उनके पास कोडिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि एनईईटी शहरी छात्रों को असंगत रूप

हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे कुचल सकते हैं?

वक्फ बिल को लेकर केंद्र पर बरसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के खिलाफ विधेयक को पारित होने पर विपक्ष द्वारा कड़ी आपत्ति जताए जाने के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को केंद्र की नारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने मद्रास को बंद करने पर प्रकाश डालते हुए परमांदा मुसलमानों के लिए सरकार की चिंता पर सवाल उठाया जहां उन्होंने कहा कि गरीब बच्चे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वक्फ संशोधन



सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। मसूद ने एनआईडी से कहा कि समानता के अधिकार को पुनर्विचार करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे कुचल सकते हैं? आप परमांदा, गरीब मुसलमानों की बात करते हैं।

आपके पास संविधान का बदलने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप इसे आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच, माज्या सांसद जगतबिका पास ने संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पारित करने के बड़े सुधार की सराहना करते हुए कहा कि वक्फ समितियों को एक मॉडल में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जिसे जल्द ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के लिए संविधान पर विरुद्ध विधायक और अस्पताल खोलने में विफल रहा। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों के बच्चे केवल कुच ही लोग इसका लाभ उठाने में कामयाब रहे हैं।

चुनावों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाएंगे...

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद से होगी डीके शिवकुमार की छुट्टी?

बंगलुरु। कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर रस्ताकरी शुरु हो गई है। कर्नाट राज्या, सतीश जारकीहोले और एमबी पाटिल जैसे मंत्रियों के एक ग्रुप दिल्ली में डेटा वाले हुए हैं और पार्टी हाईकमान से उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष के रूप में बदलने का आग्रह कर रहे हैं। उनका तर्क है कि शिवकुमार जो पहले से ही उपमुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद को संभाल रहे हैं, पार्टी के आगामी स्थानीय निकाय और बृहत बंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) चुनावों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाएंगे।



हालांकि, दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। पार्टी के पास सिर्फ तीन राज्यों में सत्ता है, इसलिए हाई कमान कर्नाटक को सिर्फ एक गढ़ के तौर पर नहीं बल्कि गारंटी प्रवेश जैसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर भी देखता है। उचित नेतृत्व

को डर है कि इस समय कोई भी बदलाव गलत संकेत दे सकता है और पार्टी ने दूसरे राज्यों में जो गति पकड़ी है, उसे बिगाड़ सकता है। संगठन के भीतर शिवकुमार की बड़ती मौजूदगी का सवाल भी है। उन्होंने न केवल कर्नाटक में 2019 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी को पुनर्जीवित करने में मदद की है, बल्कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में नाजुक बदलावों को संभालने के लिए नेतृत्व द्वारा उन पर भरोसा भी किया गया है। उन्हें बदलने से न केवल कर्नाटक में आंतरिक कलह शुरू हो सकती है - बल्कि इसका असर पार्टी के राष्ट्रीय बांधे पर भी पड़ सकता है। शिवकुमार ने खुद कहा है कि अगर पार्टी बांधी तो वह बदलाव का विरोध नहीं करेगा, लेकिन उनके समर्थकों ने उस बात पर संदेह जताया है कि उनकी जगह कौन प्रभावी रूप से ले सकता है। सिद्धार्थनाथ एमके पसंदीदा पूर्ण राज्य कांग्रेस प्रमुख दिनेश गुंडु राव का नाम सामने आया है - लेकिन कई लोगों को याद है कि 2019 में उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी।

वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में उठापटक

5 नेताओं का इस्तीफा, संजय झा बोले- जो पार्टी छोड़ रहे उन्हें हम भी नहीं जानते

पटना। जेडीयू के एक अन्य नेता नदीम अख्तर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह वक्फ संशोधन विधेयक को पार्टी द्वारा समर्थन दिए जाने के कारण पार्टी छोड़ने वाले पांचवें सदस्य बन गए हैं। उनके इस्तीफे के बाद जेडीयू नेता राजू नैयर, तबरेज निरीकी अलीग, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी सहित चार अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जेडीयू नेता राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा था, 'वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और उत्तमा समर्थन किए जाने के बाद मैं जेडीयू से इस्तीफा



देता हूँ। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का इस पर बड़ा बयान आया है। संजय झा ने कहा कि जिन मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू से इस्तीफा देने का ऐलान किया

है, उन्हें यह खुद नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल वक्फ समितियों को कुप्रबंधन को दूर करने के लिए लाया गया था। बिहार में हुई जाति जनगणना में परमांदा मुसलमान अंसारी, मंसूरी

संभूत लुट लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एडवोकेट) ने भाजपा के सहयोगी दलों और सांसदों समेत सभी धार्मिक राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का आग्रह किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विचार के मुख्यमंत्री नैतीश कुमार को संबोधित एक पत्र में तबरेज निरीकी अलीग ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के विपक्ष को छोड़ा दिया है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि वे इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुझान ने लाखों मुसलमानों को घाहरी ठेस पहुंचाई है।

यूएस टैरिफ: विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस बोली, यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा हमला

नई दिल्ली। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। शिवासेना (यूबीटी) सांसद अरवि सावत ने कहा कि टैरिफ अब क्या हुआ है। अमेरिका ने हम पर



बड़ा हमला होगा। हम इस पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सरकार संसद बंद करके भाग रही है। वित्त मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और टैरिफ के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद के.के. सुधाकर ने कहा कि फल भी हमने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष के नेता ने भी इसे उठाया था।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा हमला होगा। हम इस पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सरकार संसद बंद करके भाग रही है। वित्त मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और टैरिफ के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद के.के. सुधाकर ने कहा कि फल भी हमने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष के नेता ने भी इसे उठाया था।

गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, शिक्षा के लिए चारो तरफ से रास्ता खुला छोड़

दैनिक बुद्ध का संदेश
भारतभारी/सिद्धार्थनगर।
मुख्यमंत्री उ०प्र० योगी आदित्यनाथ ने जनपद के गुरु गोस्वामि ज्ञान स्थली, पुन्दापन, नगर पंचायत भारतभारी के शिलापट का अनावरण किया गया। साथ ही गुरु गोस्वामि ज्ञान स्थली, पुन्दापन, नगर पंचायत भारतभारी मदन का शीत काटकर उद्घाटन किया गया तथा गुरु गोस्वामि की मूर्ति का अनावरण किया गया। पूर्ण विधायक दुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं विद्यालय परिवार द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री उ०प्र० योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया।



मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया को करुणा और अहिंसा का संदेश देने वाले राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर इस जनपद का नाम सिद्धार्थनगर पड़ा है। इस धरती को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आज बसन्तीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज मां काली की आराधना होती है। आज इस ज्ञान स्थली का लोकार्पण हो रहा है। इसको लिए मैं सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत की परम्परा में शिक्षा के लिए चारो तरफ से रास्ता खुला छोड़े। ज्ञान ही जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन के आलौकिक होने का स्वागत करना चाहिए। जीवन में किसी

को ज्ञानदान बनाने से अच्छा कुछ नहीं है। कई वर्षों बाद मुझे यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2008 से पहले यहाँ बहुत चुनौतियाँ थीं। चारो तरफ असुखा का वातावरण था। शिक्षा के लिए जितना भी किया जाये कम है। शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय धरती नहीं होता है। पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने भारत को बदलते देखा है। आज नया भारत है। एक भारत है श्रेष्ठ भारत है। आज भारत किसी का पिछलग्नु नहीं है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। विरासत और पहचान के रूप में

देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में श्रीराम मन्दिर का मध्य निर्माण हो रहा है। प्रयागराज में 68 करोड़ लोगों ने कुम्भ में स्नान किया है। यह भारत की सामर्थ्य को प्रस्तुत करते हैं। अपने चौदावें की ताकत का एहसास करते हैं। भारत की संस्कृति में किसी पर बल पूर्वक अधिकार करना नहीं है। श्री राम ने रावण का ब्रह्म कर वहाँ विभीषण का राज्याभिषेक किया। बालि का ब्रह्म कर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। किसी भी कालखण्ड में तलवार के बल पर किसी पर शासन नहीं किया है। राजकुमार सिद्धार्थ ने बचपन का समय इसी धरती पर

व्यतीत किया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ समय लुम्बिनी में रहे। बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया के बहुत से बड़े-बड़े देश हैं। बुद्ध ने तलवार के बल पर नहीं अपितु अपनी शिक्षा के बल पर उन्हें अपना अनुयायी बनाया। ज्ञान की परम्परा को जानने के लिए हम सभी को ढेंढों और उपनिषदों को देखना चाहिए। उस पर काम करने की आवश्यकता है। जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ

रहा था उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020 नई शिक्षा नीति लागू की गयी। आज अमृदय योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। अटल आभासी विद्यालय की शुरुआत की गई है। प्रदेश में 17 अटल आभासी विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। कस्तूरबा गांधी आभासी विद्यालयों को भी अपरोध किया गया है। गुरु गोस्वामि ज्ञान स्थली, पुन्दापन, नगर पंचायत

भारतभारी में भी 150 छात्र/छात्राओं द्वारा नये सत्र के लिए पंजीकरण कराया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ज्योति सिद्धार्थ पिन्धविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर प्र०0 कविता शाह ने गुरु गोस्वामि ज्ञान स्थली, पुन्दापन, नगर पंचायत भारतभारी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि आज मुख्यमंत्री उ०प्र० योगी

आदित्यनाथ मंच पर हैं। जिन्होंने पूरे उ०प्र० की दिशा और दशा बदली है। शिक्षा के जगत में सिद्धार्थ विश्व विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है। एक राष्ट्र, समाज और परिवार का विकास बिना शिक्षा के सम्भव नहीं है। सिद्धार्थ विश्व विद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त अवसर प्राप्त करेगा। श्री अम एण सेवायोजन समन्वय/जनपद प्रमार्थ मंत्री अनिल राजमर ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा 01.04.2025 को जनपद बरेली में अटल आभासी विद्यालय का लोकार्पण किया गया है। इस विद्यालय में मजदूर, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कावाकल्प योजना चलाकर विद्यालयों में काम किया गया है। इन विद्यालयों में मजदूर एवं गरीब का बेटा पढ़ता है। आज विद्यालयों में पंखा चल रहा है। बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है। परिवर्तित विद्यालयों में सर्टाट क्लास मौ चल रहा है। मुख्यमंत्री की प्रामुखिता है कि सभी को शिक्षा मिले। श्री ने कहा कि मैं सभी की तरफ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पूर्ण विधायक दुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि आज मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने पिछले महीने ही मुख्यमंत्री अनुरोध किया कि आप को विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आना है। मुख्यमंत्री मेरे अनुरोध को स्वीकार कर समय दिया। मैं सभी की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। 1994 से मैं आपके सानिध्य में ही सब सीखा है। मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि सिद्धार्थनगर में गुरु गोस्वामि के नाम से विद्यालय खुले। मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री आप इस विद्यालय के मुख्य संरक्षक होना स्वीकार करें। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यहाँ पर जो भी विद्यालय थे अपनी संस्कृति के नहीं थे। इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्ण विधायक इटवा बड सतीश द्विवेदी, जिला प्रमारी हरिचरण कुशाहा, अमर पुलिस महा निदेशक गोरखपुर जौन गोरखपुर ड०0 के०एस० प्रताप कुमार, आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती जयलेश कुमार सिंह, डीआईजी दिनेश कुमार पी, जिलाधिकारी ड०0 राजा गणपति अग्र, पुलिस अधीक्षक ड०0 अभिषेक महाजन अमर जिलाधिकारी (पी०/रा०) गौरव श्रीवास्तव, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, दूर-दराज से आयी जनता तथा स्थली बच्चों आदि की उपस्थिति रही।

लीलावती देवी महिला पी जी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी का आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। लीलावती देवी महिला पी जी कॉलेज पेशावे बुजुर्ग सिद्धार्थनगर में 'मिश्राशक्ति' कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण में डॉ० के.अर.अब्दुल का उद्घाटन विध पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें रतन सेन द्विवेदी कॉलेज बस्ती सिद्धार्थनगर संस्त प्रिमाग जी एसोसिएट प्रोफेसर डॉ० किचन देवी ने छात्राओं को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा की आज बाबा साहब के संविधान ने हम सभी को पढ़ने सिखने बोलने का अधिकार दिया है जिससे छात्राएँ उच्चशिक्षा के



क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकें जिसमें बहुत सारी छात्राओं ने

कैरियर बनाने हेतु मार्गदर्शन किया इसी क्रम में प्रबंधक डॉ० पेट प्रकाश पाण्डेय ने कहा यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का एक मात्र महिला महाविद्यालय है जहाँ दिनत 10 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह लीलावती देवी महिला महाविद्यालय एक कीर्तिमान स्थापित किया है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दो-दो पीढ़ियाँ शिक्षा से वंचित रही है ऐसे बच्चियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सशक्त कर दिया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित और प्रेक्षा पाण्डेय सर्वश्री पाण्डेय शिषु मिश्रा सुजीत यादव आदि लोग उपस्थित रहे हैं।

बड़-बड़कर अनेको सवाल कैरियर को लेकर के किया जिसमें डॉ० किचन देवी ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में

शक्ति पीठ पल्टा देवी मंदिर में मणेंद्र मिश्रा मशाल ने किया फलाहार कार्यक्रम का आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश
शोहरतगढ़। शोहरतगढ़ शिवानसमा में पांडशकालीन शक्ति पीठ पल्टा देवी मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्रि सप्तमी के अवसर पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी विचक समा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेंद्र मिश्रा मशाल ने किया। कार्यक्रम में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पाण्डेय ने श्रद्धालुओं को फलाहार/प्रसाद वितरण का प्रारंभ किया। मां मशाली के दर्शन उपरंत श्री पाण्डेय और आयोजक मणेंद्र मिश्रा ने पल्टा देवी मंदिर के मध्या सर्वश्री घनरघाम गिरी



महाराज, मध्या टीनानाथ गिरी मंदिर परिवार को छादी वस्त्र एवं फल भेंट किया। नेता विरोधी दल श्री पाण्डेय ने समस्त क्षेत्रवासियों के शान्ति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना किया। कार्यक्रम के आयोजक मणेंद्र मिश्रा मशाल ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि अतिशक्ति मां दुर्गा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। कार्यक्रम में सर्वश्री पूर्ण विधायक अनिल सिंह, परिवेद नेता सुरजीत वर मिश्रा, जिला सचिव हरिचरण यादव राष्ट्रीय सचिव लोहिवा याहिनी राघवेंद्र बुबे अजय चौरसिया राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा, नितिन शिवादी, सेक्टर प्रमार्थ सुनील यादव एवं अर्जुन यादव सुरज नाथर, संदीप सहनी सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे।

अखिलेश यादव के गाय, गोबर और गौशाला के राजनितिक बयान से क्षुब्ध है यादव समाज:सुभाष यदुवंश

दैनिक बुद्ध का संदेश
शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर।
शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने नई दिल्ली में गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। सुभाष यदुवंश ने कहा की मोदी जी का शासन काल भारतीय इतिहास का यह सुनहरा पन्ना है जिसे पहकर देश की पीढ़ियाँ गर्व, साहस और प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। आज आपके और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक बिल पास होने से सभी देशवासियों



न इसका स्वागत किया है। इस और एक सपत्तियाँ अधिक बिल के पास होने से परमांडा समाज और कमजोर वर्ग के नुसलमान समाज को बहुत लाभ होगा। इसीलिए समाज के सभी वर्गों द्वारा इसका स्वागत किया गया है। शक्य (संशोधन) विधेयक 2025 के मध्यम से वर्षों से चले आ रहे अन्धाध और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से एक बोर्ड

जबाबदारी, पारदर्शी और न्यायसंगत होने वाली है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के

गरीबों महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। ये बिल इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज आपके कुशल नेतृत्व में सैकड़ों सालों से चले आ रहा नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर। अशिकांश न क स ल ड। टी आत्मसमर्पण कर मृत्यु दारा मे आ रहे सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बन रहा है। विश्व आज किसी भी समस्या के समाधान के लिए भारत देश से मदद की उम्मीद करती है। स पूरे विश्व में भारत देश में उका बज है। भारत देश विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। सुभाष यदुवंश ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जबकि पिपली दल आईएमवी.आईए (इंडिया) नाम से गठबंधन कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नाम बदल लेने से नियत साज नहीं हो जाती स लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा,

महाप्रायद पुनाप में प्रचंड विजय से ये तप होता है कि पूरा देश आज भी मोदी जी नीतियों और विकास से सजुब है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जनवार चुटने ही चुका है उन्हें जनता के मतलब है। उनकी नकारात्मक राजनीति प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। अखिलेश यादव ने बोला कि उन्होंने गाय गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है इससे संपूर्ण यादव समाज समावन धर्म और धर्मपालक समाज का इदय बहुत मरमहत है अखिलेश यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

महाराज, चंदन गिरी, शंभुनाथ गिरी को शाल सहित समस्त 37

परिषदीय विद्यालय तिवारीडीह में बच्चों में वितरित हुआ पाठ्यपुस्तक



दैनिक बुद्ध का संदेश
उत्का बाजार। अक्षय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित परिषदीय विद्यालय तिवारीडीह में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामप्रधान मनोज साहनी ने बच्चों में नि:शुल्क पुस्तक का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत से ही परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की हठों में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा की बहुत खुशी है कि इस बार सत्र शुरू होते ही बच्चों को पुस्तकें मिलनी लगी। परिषदीय विद्यालयों में गॉय शिक्षक तैनात हैं। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चों को नियमित विद्यालय भेजना चाहिए और घर पर भी शिक्षण कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। ग्राम प्रधान ने शिक्षकों का आभारन किया कि वे समाज में परिषदीय विद्यालयों के प्रति ध्यान बनाने के लिए संज्ञा रहे। प्रधानाध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सभी अभिभावक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन परिषदीय स्कूलों में कराए। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार कई तरह की योजना बनाकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर बुद्धिगाम, राम सेवक, राम शब्द, पिटू दूरे अनंत मिश्र आदि रहे।

महिला थाना ने 03 परिवार के मध्य सुलह समझौता करारकर परिवार को बिखरने से बचाया



दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ड०0 अभिषेक महाजन के निदेश पर शुक्रवार को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण (दुर्घट परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 05 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुईं। जिसमें परामर्श के बाद 03 पत्रावली का सकल निस्तारण कर 03 परिवार को बिखरने से बचाया गया व 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 03 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष शाइस्ता, उप निरीक्षक रामनारायण शुक्ला, महिला हेड कांस्टेबल सत्या त्रिपाठी, महिला हेड कांस्टेबल सविता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं निस्तारित पत्रावली में सुशांशु पत्नी दयाराम निवासी राम बसुलपुर थाना बांसी, आरती पत्नी शैलेका निवासी राम गोसाईगंज थाना मोहना एवं आरिया पत्नी सेराज निवासी रेशक बाजार सुभाष नगर थाना, उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर थी।

जिसमें परामर्श के बाद 03 पत्रावली का सकल निस्तारण कर 03 परिवार को बिखरने से बचाया गया व 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 03 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष शाइस्ता, उप निरीक्षक रामनारायण शुक्ला, महिला हेड कांस्टेबल सत्या त्रिपाठी, महिला हेड कांस्टेबल सविता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं निस्तारित पत्रावली में सुशांशु पत्नी दयाराम निवासी राम बसुलपुर थाना बांसी, आरती पत्नी शैलेका निवासी राम गोसाईगंज थाना मोहना एवं आरिया पत्नी सेराज निवासी रेशक बाजार सुभाष नगर थाना, उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर थी।

सम्पात्कीय

कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना चिंताजनक

यह विडंबना है कि नागपुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगायी थी, लेकिन जब तक आदेश पहुंचा तब तक स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर चुका था। वैसे हकीकत यह भी है कि कोई अवैध निर्माण रातोंरात खड़ा नहीं हो जाता। जब उसका निर्माण होता है तो स्थानीय ...

यह पहली बार नहीं है कि देश की शीर्ष अदालत को कहना पड़ा कि कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई न्याय के नैतिक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ऐसी बलपूर्वक की गई कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर की नाईसानी नजर आई। कोर्ट का कहना था कि यह बुलडोजरी अत्याचार केवल सुविधाओं व मकानों को ही नहीं गिरा रहा है बल्कि यह कानून की उचित प्रक्रिया व अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण है। जो हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुझा की गारंटी देता है। शीर्ष अदालत ने प्रयागराज में घरो को गिराए जाने को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए हाथी विकास प्राधिकरण को प्रत्येक मीटिंग घर के मालिक को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घटी उस घटना को तंत्र की संबन्धीता बताया जिसमें बुलडोजर द्वारा झोपड़ी गिराए जाने पर एक बालिका अपनी किताबें फेंककर भाग रही थी। अदालत का कहना था कि तत्पश्चात् देश की अंततः को फलदायी देने वाली है। साथ ही अधिकारियों की मनमानी और असंवैधानिकता को उजागर करती है। कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को बुद्ध की स्थिति को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिए बिना बुलडोजर से उनके मकान या झोपड़ियों को ध्वस्त करना अत्याचार जैसा ही है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन का दुरादा अनधिकृत निर्माण को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें सबक सिखाना लगता है। दूरअसल उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन कथित तत्काल न्याय के बुलडोजर मॉडल को लागू करने में सक्षम आगे रहा है। इस विषयादास्य कार्रवाई का बचाव करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कमी-कमी कुछ लोगों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में चीजों को समझाने की जरूरत होती है। जिसके साथ ही यह भी है कि ऐसे तत्वों को अदालतों द्वारा उन्हें टोपी या निर्दोष ठहराये जाने का इंतजार किए बिना ही टूटित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते साल नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने

बुलडोजर के लगातार इस्तेमाल पर रोक लगाने के सिधे कई टिका-निर्देश दिए थे। इसमें मकान आदि के ध्वस्तकरण से पहले कब्जाधारियों को संकेत करना भी शामिल था। अदालत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि निर्देशों का अतिक्रमण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपमानना की कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं आया। इसमें दो राय नहीं कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य-सहिष्णुता का नजरिया जरूरी है। अवैध निर्माण हटाया जाना चाहिए लेकिन सभी कार्यदे-कानूनों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अदालत मानती रही है कि जल्दबाजी में बुलडोजर का इस्तेमाल असंवैधानिक है और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। प्रयागराज व महाराष्ट्र में कई जगह लोगों ने आरोप लगाया कि नोटिस देने के चौबीस घंटों में ही उनके मकान गिरा दिए गए। ऐसी ही कार्रवाई नागपुर हिंसा के बाद आरोपियों के घर गिराने में की गई। कहा गया कि लोगों को अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया। वैसे यह नैतिक न्याय की अवहेलना है कि एक कथित दोषी के कुत्तों की सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है। उस घर में उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। यह विडंबना है कि नागपुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगायी थी। लेकिन जब तक आदेश पहुंचा तब तक स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर चुका था। वैसे हकीकत यह भी है कि कोई अवैध निर्माण रातोंरात खड़ा नहीं हो जाता। जब उसका निर्माण होता है तो स्थानीय प्रशासन की नजर उस पर क्यों नहीं जाती। एकाएक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो जाती है कि उसे गिराने की तत्काल जरूरत पड़ती है। गिरा-गिरा बुलडोजर चल जाता है। सवाल यह भी कि हर छोटे-बड़े इलाक़े में प्रभावशाली नेताओं के अवैध निर्माण पर पीला पना क्यों नहीं चलता? निस्संदेह, बुलडोजर की गति राजभ्रम के संज्ञान में ही तेज होती है।

माता दुर्गा के सभी नौ स्वरूपों की जय बोलिए



प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तृतीय चन्द्रमहादेवि कृष्णमण्डेति चतुर्थकम् ॥ पंचम स्कन्दमहादेवि बह्व काल्याणनीति च। सप्तम कात्तारशक्ति महागौरीति चाष्टमम् ॥ नौवीं दुर्गा माता सिद्धिदात्री हैं। माता दुर्गा देवी सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करती हैं। उनका दुर्गा देवी की अन्त महिमा है। उनके सभी नौ स्वरूप अत्यंत गौरवशाली हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा चौथी कुम्भादा, पांचवी स्कंध माता, छठवीं काल्याणिनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री हैं। ये मां दुर्गा के नौ रूप अत्यंत समकारिणी हैं। सभी देवी-देवता और ऋषि-मुनि महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होने लगे थे। तब मगधन सिंध और मगधन विष्णु ने सभी देवताओं से परामर्श करते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें एक शक्ति को प्रगत कर महिषासुर का वध किया जा सके। सभी देवताओं ने एकसाथ मिलकर एक तेज के रूप में शक्तिस्वरूप मां दुर्गा देवी को प्रकट किया। माता दुर्गा देवी हिंदुओं की सर्वाधिक शक्तिशाली देवियों में से एक हैं। हिंदू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि माता दुर्गा देवी, अमृतोपानी राक्षसों का वध करने के लिए ही आई थीं। पुरुष देवता असुरों को नियंत्रित करने में सफल रहे और तब उन्हें बनाया गया। उनको पास सभी पुरुष देवताओं की संयुक्त शक्तियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के इन नौ दिनों में मां दुर्गा की व्यक्ति सम्भूत मन से पूजा अर्चना करता है। उसके घर में सदैव माता दुर्गा देवी की का दास होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपके पास 9 दिनों के विशेष समय होते हैं। माता दुर्गा देवी के आस्थापन हेतु कई मंत्र हैं। इनमें से कुछ मंत्र इस तरह हैं: देविए और सन्याय कौजिए। सर्वमाल सागव्ये शिष्टे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये प्रबन्धे गौरी नारायणि ममोत्सुते ॥ ६ जपनी मंगला काली मदकाली कपालिनी। दुर्गा समा शिवा वात्रे स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ॥ माता के आस्थापन हेतु नवरात्रि मंत्र ३ ६ ९ ही बली चामुण्डाये शिवा ३ का जप करें। पिण्डज प्रसाद चन्द्रकोमलसुता। प्रसीदत तनुते महि चंद्रघण्टातिरक्ता। देहि सौम्य आरत्यं देहि मे पद्म सुखं। क्वं देहि जयं देहि यशो देहि विघ्नजहि। दुर्गा स्तुता हवामि मीतिरेवजन्तो स्वस्थे स्तुता मीतमतेषु शुभा ददासि सृष्टिस्थितिनिदानां शक्तिभूते सनातानि। गुणधर्मै गुणमते नारायणि नमोऽस्तुते ॥ नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन सभी स्वरूपों के अलग-अलग मंत्र हैं। इन मंत्रों को पूजा-पाठ के दौरान जपना होता है। माता दुर्गा देवी की जय। जय माई की।

लेखक विनय जांत सिंह / डैनिक बुद्ध का संदेश

राजनीतिक इच्छाशक्तिकी कमी से संकट बरकरार

हालात यह है कि कहीं शोधन संयंत्र देखभाल के अभाव में खराब पड़े हैं, कहीं उनकी शोधन क्षमता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कहीं जरूरत के मुताबिक उनकी तादाद बहुत कम है, और कहीं बिजली आपूर्ति समय पर न होने के कारण वे पूरे समय काम नहीं कर पाते। कहीं-कहीं शोधन संयंत्रों से गंदे नाले जोड़े ही नहीं गए हैं, नतीजतन वे सीधे नदियों में गिर रहे हैं...

इन्फेक्ट राफ्ट बीते दिनों महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (नरसे) प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा की स्वच्छता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश की कोई नदी ऐसी नहीं है जो स्वच्छ हो और प्रदूषण मुक्त हो। विडंबना यह है कि इसके बावजूद हम उन्हें स्वच्छ रखने में असफल रहे हैं। गौरतलब है कि गंगा की सफाई का जिम्मा केंद्र सरकार के खात मंत्रालय पर है, लेकिन हकीकत यह है कि गंगा अपने मायके से ही प्रदूषित हो रही है। उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि गंगा कई स्थानों पर जल शोधन संयंत्र से छोड़े गए पानी से ही प्रदूषित है। एनजीटी को भी इस बारे में जानकारी है। यह स्थिति केवल गंगा की नहीं बल्कि देश की दूसरी नदियों की भी है।

एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों में रोजाना 1100 मिलियन लीटर प्रति दिन (एएमएलडी) औषध गिर रहा है। राज्य में गंगा ट्रीटमेंट के अपरिपक्व पदार्थ खुलेआम गिराए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि यहां एक-तिहाई क्षमता से एस्टीपी काम कर रहे हैं और 11 क्लस्टरों के लिए पर्यट ही नहीं हैं। इसके लिए एस्टीपी की क्षमता तीन गुना बढ़ानी होगी और निगरानी तंत्र को चौकस करना होगा। तभी कोई बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

गौरतलब है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यमुना में प्रदूषण के लिए 80 फीसदी जिम्मेदार नजफगढ़ नाले को मानती है। असलियत यह है कि यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि दिल्ली के अंदर और सीमा पर भी उसका जल नहाने लायक नहीं है। आंकड़ों के अनुसार एक समय देश में करीब 15,000 छोटी-बड़ी नदियाँ थीं, जिनमें से 30 फीसदी से ज्यादा आज सूख चुकी हैं। 4500 से ज्यादा छोटी या मझोली नदियाँ केवल बारिश के दिनों में बहती हैं और बाकी आठ-तीन महीनों में वे मृतप्राय रहती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना में बरसलत के दिनों में भले जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन बाकी आठ-तीन महीनों में इसका जलस्तर काफी कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में स्थिति और मजबूत हो जाती है। यही हालत देश के अन्य राज्यों की छोटी-बड़ी नदियों की है जहां की नदियों के

समा-साथ झीलों का जलस्तर भी कम हो गया है। उत्तराखंड में पर्यटन के लिए विख्यात नैनीताल की झीलें इसकी जीती-जागती मिसाल हैं जिनका जलस्तर कम हो रहा है। मध्य भारत की गंगा कहलाने वाली पौराणिक नदी बेतवा की बात करें तो उसके उद्गम स्थल ही सिमट गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 में बेतवा के उद्गम स्थल में जल गंगा संयोजन योजना शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन उसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सवाल यह है कि देश की नदियाँ साफ क्यों नहीं हो पा रही हैं। इस मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि इसमें सीवेज सिस्टम की खामी अहम कारण है। असलियत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सीवेज सिस्टम में सुचारु में नाकामी के कारण सीवेज का गंदा पानी सीधे नदियों में गिरकर उन्हें विषाक्त कर रहा है। इसके लिए उन शहरों के नगर निकाय पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हालात यह है कि कहीं शोधन संयंत्र देखभाल के अभाव में खराब पड़े हैं कहीं उनकी शोधन क्षमता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कहीं जरूरत के मुताबिक उनकी तादाद बहुत कम है और कहीं बिजली आपूर्ति समय पर न होने के कारण वे पूरे समय काम नहीं कर पाते। कहीं-कहीं शोधन संयंत्रों से गंदे नाले जोड़े ही नहीं गए हैं नतीजतन वे सीधे नदियों में गिर रहे हैं।



किनारे बसे जिलों के 225 नाले सीधे नदियों में मिल रहे हैं जबकि केवल 101 नाले एस्टीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जुड़े हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यमुना में प्रदूषण के लिए 80 फीसदी जिम्मेदार नजफगढ़ नाले को मानती है।

कुछ ही दिन पहले एक प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी में कहा था कि कलाकार, साहित्यकार का (अभिव्यक्ति की आजादी) अधिकार इस आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता कि उनकी अभिव्यक्ति कितनी लोकप्रिय है। विचार का मुकाबला विचार से ही होना चाहिए। इसी टिप्पणी में आगे यह भी कहा गया कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर ...

दिरघमंच सचदेव एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा चर्चा में है और इसे एक विडंबना ही कहा जायेगा कि इस बार यह मुद्दा एक कॉमिडियन की प्रस्तुति को लेकर उठा है। मैं बात कुणाल कामरा के उस कार्यक्रम की कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के एक राजनेता को गटार कहा था। यह पहली बार नहीं है जब एक नेता को किसी ने इस विशिष्टण से जोड़ा है। एक नेताजी के पुराने साथी, जिसने त्याग कर उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनायी थी, अक्सर उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते रहे हैं। पर नेताजी के अनुयायियों ने अब अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की हैकुछसे पहले नहीं देखा गया था।

जहां तक कॉमिडियन की बात है मुझे आपत्ति किसी को गटार कहने से नहीं है। कोई भी नेरी नजर से देखेंगे का धास्ता देकर किसी पर इस तरह का आरोप लगा सकता है पर दुझे उन गतिियों से आपत्ति है जो कॉमिडियन अपने कार्यक्रम में काम में लेते हैं। वह भाषा किसी सम्य समाज की नहीं होनी चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि व्यंग्य सार्थक भी तभी होता है जब जिसपर व्यंग्य किया गया है, वह तिल मिलाकर रह जाये और अपने आप को कुछ करने की स्थिति में नौ नहीं परते। बहरहाल इस सबके बावजूद मैं कॉमिडियन के अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मन करूंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। यही इस बात को भी रेखांकित किया जाना जरूरी है कि यह अधिकार असीमित नहीं है। हमारा संविधान इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध की बात भी करता है। जहां एक ओर इस अधिकार का उपयोग करने वाले से विवेकशील होने की अपेक्षा की जाती है। वहीं यह बात भी जरूरी अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रीय हितों को देखते हुए उचित प्रबंध लगाये। हां यह बात भी सही है कि अक्सर सरकारें अपने इस अधिकार का गलत उपयोग करने लगती हैं। अक्सर हम यह भी देखते हैं कि अभिव्यक्ति



की स्वतंत्रता के खतनों की दुहाई देकर जनतंत्र के इन महत्वपूर्ण हथियार को नष्ट करने की कोशिशें होती हैं। पचास साल पहले जब देश में आपातकाल घोषित किया गया था तो तब की सरकार ने ऐसी ही एक कोशिश की थी। यही यह बात भी जरूरी है कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को स्वीकार भी था कि संसदीय के कारण उन तक सही और पूरी जानकारी नहीं पहुंच पायी थी और वे उचित कदम नहीं उठा पायीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अति

लोकतंत्र की आत्मा है अभिव्यक्ति की आजादी

होकार के इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। जनतांत्रिक व्यवस्था में जहां यह अधिकार जनता को एक हथियार देता है वहीं संबन्धित सरकार को भी अपना कर्तव्य निभाने में सहायता कर सकता है। इस अधिकार का अभाव या हनन दोनों जनतंत्र को कमजोर बनाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी परकार को दिवंगे गये इंटरव्यू में आलोचना को जनतंत्र की आत्मा कहा था। तब उन्होंने यह भी कहा था कि आज के जमाने में सही और तीखी आलोचना दिखाई नहीं देती। इसी इंटरव्यू में उन्होंने भारत में आलोचना की शानदार परंपरा का भी उल्लेख किया था। निटक निचरे राशिष्ट वाले कबीर को भी याद किया था। अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने आलोचना और आरोप में अंतर समझाने की भी कोशिश की थी। यह बात टिप्पण देने वाली है। पर अपने एक टिशक से अधिक के कार्यकाल में एक भी प्रेस ऑफेंस न करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने आलोचना के द्वार को ही जैसे बंद कर रखा है। परकारी रचनाकारों के प्रति एक आदरभाव की अपेक्षा करती है जनतांत्रिक व्यवस्था। यदि रचनाकार, परकार, व्यंग्यकार आलोचना करते हैं तो व्यवस्था का टाटित्व बनता है कि यह इसे सकारत्मक दृष्टि से समझ-सुझाकर। यहा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाना चाहिए। जब उन्हें यह लगा कि उनकी समुचित और सार्थक आलोचना नहीं हो रही

तो उन्होंने छद्म नाम से स्वयं अपनी आलोचना करके जनतांत्रिक तौर-तरीकों का जैसे सास्ता दिखाया था। यही नहीं, उस जमाने के जाने-माने बरिष्ठ काटूनिस्ट शंकर को एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने कहा था, शंकर मुझे भी मत झुझाना। नेहरू का यह दृष्टिकोण और कथन जनतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के सम्मान का एक उदाहरण है। इतिहास साक्षी है कि काटूनिस्ट शंकर ने और उसके बाद आरके लक्ष्मण ने अपनी कृतियों में सकारात्मक आलोचना के डेरों उदाहरण प्रस्तुत किये थे। एक और काटूनिस्ट थे जाक। उनके काटूनि भी सत्ता की तीखी आलोचना करने वाले हुआ करते थे। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। यहां व्यंग्यकार शरद जोशी को याद करना भी जरूरी है। शासन को सही राह पर लाने की एक सार्थक कोशिश हुआ करता था उनका लेखन। उनके व्यंग्य इसलै भी थे और तिलमिलाने भी थे। यहीं यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इन और ऐसे आलोचकों को उचित प्रतिसाद देना शासन और समाज दोनों का कर्तव्य है।

जनता त्रिक रचरचना। मात्र शासन-व्यवस्था नहीं है यह एक जीवन-पद्धति है। इस व्यवस्था में सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य बनता है कि वे कर्तव्यनिष्ठा और जागरूकता का निस्तार उदाहरण प्रस्तुत करें। इसी प्रक्रिया का हिस्सा आलोचना को सम्मान देना है। इसी सम्मान का प्रतीक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ दोहराने की की

